VNK-KGG/2F/4.00

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग का कोई एक प्रकार का चरित्र नहीं कह सकते हैं।...(व्यवधान)... यह देश बहुत बड़ा है, यह देश बहुत बड़ी भौगोलिक विशेषताओं को लिये हुए हैं, इसलिए यहां पर मध्यम वर्ग आय से भी है, मध्यम वर्ग की कल्पना शिक्षा के माध्यम से भी है, मध्यम वर्ग की कल्पना व्यवसाय के माध्यम से भी है।...(व्यवधान)... मध्यम वर्ग की कल्पना इस माध्यम से भी है कि वह किस सोसाइटी में रहता है, मध्यम वर्ग की कल्पना इस माध्यम से भी है कि वह किस प्रकार की जीवन शैली को जीता है, लेकिन इन सारे मध्यम वर्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं, जब हम सबको आधारभूत ढांचा सही से देंगे।...(व्यवधान)... इस मध्यम वर्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं, जब शिक्षा में जो मौलिक सुधार चाहिए, उन सुधारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।...(व्यवधान)...

(उपसभाध्यक्ष, श्री तिरुची शिवा पीठासीन हुए)

इस मध्यम वर्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं, जब जिस प्रकार से देश में नये innovative ideas चाहिए, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा साधनों का प्रयोग कर सकें।...(व्यवधान)... इस मध्यम वर्ग को हम तभी बढ़ा सकते हैं, जब जिस स्थिति में वे काम कर रहे हैं, उनका स्किल अपग्रेडेशन करने के काम को हम आगे बढ़ाएं।...(व्यवधान)... इस मध्यम वर्ग को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं, जब शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सुविधाओं की पूर्ति की जाए।...(व्यवधान)... इस मध्यम वर्ग को हम तभी बढ़ा सकते हैं, जब हायर एजुकेशन में जितने आवश्यक सुधार चाहिए, उन सुधारों को करने का काम किया

जाए।...(व्यवधान)... इस मध्यम वर्ग को हम तभी ताकत दे सकते हैं, जब लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है, उन नीतियों को आगे बढ़ाया जाए और हमारी सरकार ने इन सारे विषयों को आगे बढ़ाने का काम इस बजट के माध्यम से किया है।...(व्यवधान)... मैंने पूर्व में कहा है कि यह जो बजट है, यह केवल एक साल का नहीं ...(व्यवधान)... अगर आप चार साल के बजट में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सरकार ने एक consistency के साथ सारे विषयों को आगे बढ़ाया है।...(व्यवधान)... कम से कम आपकी तरह ऐसा नहीं किया था कि 2003 से 2008 तक fiscal deficit को लेते रहे, जब 2008-09 में चुनाव लड़ने का वक्त आया, तब आपने fiscal deficit को 6 परसेंट कर दिया।...(व्यवधान)... आपने देश में रेवड़ियां बांट कर सरकार चलाने का काम किया, लेकिन देश की जनता ने तब भी आपको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह आपके असत्य के पुलिंदे थे, जिसको इस देश की जनता ने नकारा था।...(व्यवधान)...

महोदय, मैं सबसे अंत में यह कहना चाहूंगा और मुझे इस बात का फख भी है कि हम लोग जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, जिस राजनीतिक विचार के लिए काम करते हैं...(व्यवधान)... वह पंडित दीनदयाल जी की राजनीति विचारधारा से प्रभावित होकर करते हैं।...(व्यवधान)... हम लोग एक राष्ट्रवाद के दर्शन के आधार पर काम करते हैं।...(व्यवधान)... 1952 से लेकर आज तक अगर किसी पार्टी ने अपने राजनीतिक विचारों के साथ समझौता नहीं किया है...(व्यवधान)... अगर किसी पार्टी ने सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है...(व्यवधान)... अगर किसी पार्टी ने राजनीतिक छुआछूत का काम नहीं किया है, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता

हूँ कि हिन्दुस्तान के राजनीतिक आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है, जिसने देश में बिना राजनीतिक छुआछूत के राजनीति की है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Why don't you go back to your seats? ...(Interruptions)... Go to your seats, please. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में जब से गवर्नेंस की राजनीति आई है, जब से सुशासन राजनीति का आधार बना है...(व्यवधान)... वह तभी से बना है, जब 1996 में भारतीय जनता पार्टी की, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, हमने पांच साल की सरकार दी।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please go to your seats....(Interruptions)... Resume your seats, please. ...(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, हमने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लगातार 15 साल तक एक सफल शासन गुजरात में दिया।...(व्यवधान)... उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमने देश की राजनीति में गवर्नेंस को एक विषय बनाया और गवर्नेंस को विषय बना कर आज हिन्दुस्तान में सुशासन की राजनीति को आगे बढ़ाया।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please go to your seats....(Interruptions)...

श्री भूपेन्द्र यादव : महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस भी प्रकार का देश का वातावरण बना है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह यह है कि हिन्दुस्तान में पिछले

70 साल की राजनीति में जिनके अधिकार थे, जिनको अधिकार देने चाहिए थे, उनको अधिकार नहीं दिए गए।...(व्यवधान)... जिन गरीबों को उनका हक देना चाहिए था, उनको हक नहीं दिया गया।...(व्यवधान)... जिन गरीबों तक उनका हक पहुंचना चाहिए था, उस हक को देने का काम नहीं किया गया।...(व्यवधान)... उन गरीबों को हक देने का काम इस सरकार ने किया है।...(व्यवधान)... सबसे पहले मनरेगा का पैसा सीधा कैश ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है।...(व्यवधान)... आज आपको लगता होगा कि हम यह जो आयुष्मान योजना लेकर आए हैं, यह इंश्योरेंस का पैसा गरीबों को कैसे जाएगा? ...(व्यवधान)... मैं आपको कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं, उन्होंने तीन साल पहले सोच लिया होगा कि अगर गरीब को पैसा भेजना है, तो पहले उसका अकाउंट खोला जाए और इसलिए दूरदृष्टि का काम प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया।...(व्यवधान)... आपको तो तीन साल पहले पता भी नहीं था कि हम जन-धन खाता क्यों खोलना चाहते हैं? हम यह इसलिए खोलना चाहते थे, क्योंकि हम गरीब को ताकत देना चाहते थे।...(व्यवधान)... हम गरीब तक संसाधन पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पर काम करती है, एकात्म मानववाद के विषय को लेकर काम करती है।...(व्यवधान)... इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो सबसे बड़ा विषय है, वह हमारा अन्त्योदय का नारा है।...(व्यवधान)...

(2जी/एनकेआर-केएलएस पर जारी)

NKR-KLS/2G/4.05

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : अन्त्योदय के नारे को आगे बढ़ाने के लिए, न केवल हमने देश में संकल्प लिया है, ..(व्यवधान).. बल्कि हम लोगों ने अपनी सरकार को उसी दिशा में चलाने का प्रयास किया है।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में कार्य किया है, जिस प्रकार की सरकार दी है, इस सरकार का लक्ष्य क्या है? ..(व्यवधान).. इस सरकार का लक्ष्य है कि -

"जो लोग अंधेरे घर में हैं,

अपनी ही नज़र में रहते हैं,

हम उनके कोने-कोने में उद्यम के दीप जलाएंगे,

जो लोग हार कर बैठे हैं,

उम्मीद मार कर बैठे हैं,

हम उनके बुझे जीवन में फिर से प्रकाश जगाएंगे।

है शौक यही, अरमान यही,

हम देश के जीवन में बदलाव लाएंगे।"..(व्यवधान)..

इस देश में भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी शासन, देश में गरीबों के हित में शासन, देश के युवाओं को रोज़गार देने वाली सरकार के रूप में शासन-प्रणाली को आगे ले जाना चाहते हैं। ..(व्यवधान).. यह सरकार, जो किसानों की सरकार है, यह सरकार जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चेहरे को बदलने का संकल्प लेकर आई है, उस संकल्प को रोकने का काम वे लोग कर सकते हैं, ..(व्यवधान).. जिन्होंने 50 सालों में अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया है। हम उस उत्तरदायित्व को पूरी संजीदगी के

साथ निभाना चाहते हैं। इसलिए देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, वह बताता है कि यह देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।..(व्यवधान).. यही इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है कि ग्लोबल कंपिटीटिव इंडेक्स इस देश का सबसे ज्यादा सुधरा है। 'Ease of doing business' के क्षेत्र में यह देश सीधे एक-साथ तीस पायदान की छलांग लगाकर ऊपर पहुंचा है। सबसे ज्यादा फॉरेन रिज़र्व इस सरकार के समय में बढ़ा है। डिमॉनेटाइजेशन के बाद, जो सबसे बड़ा काम यह हुआ है, वह है काले धन की अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाने का काम, जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। ..(व्यवधान)..आपकी सरकार के समय में ब्लैक मनी संबंधी जो व्हाइट पेपर आप लाए थे, आपने उसे लागू नहीं किया, क्योंकि आपको डर था कि सिद्धांत बनाना अलग होता है और उस सिद्धांत के आधार पर दृढ़ता से निर्णय लेना और गरीब के हित में निर्णय लेना सबसे बड़ा काम होता है। ..(व्यवधान).. इस निर्णय को लेने और आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने किया है। इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें इस बजट के लिए बधाई देना चाहूंगा कि यह बजट अपने आपमें एक अभूतपूर्व बजट है। यह कोई पहला बजट नहीं है, बल्कि लगातार इस सरकार का तीसरा-चौथा ऐसा बजट है, जिसके माध्यम से देश में प्रगति की दिशा बनी है।

आज इस आर्थिक बजट पर चर्चा करने के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का सामाजिक दर्शन भी महत्वपूर्ण होता है। ..(व्यवधान).. इस बजट में सरकार गरीबों के हित में जो योजनाएं लेकर आई है, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। आज मैं सदन में कहना चाहता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में भी जब हम ओ.बी.सी. के हित में बिल लेकर आए, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। जब हम मुस्लिम महिलाओं के

हित में बिल लेकर आए, उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया। ..(व्यवधान).. ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति सुधारने संबंधी बिल जब हम लेकर आए, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने हालांकि विरोध में मत तो नहीं दिया, लेकिन ..(व्यवधान).. विषय को जब हमने विकास में परिवर्तित करने का प्रयास किया, तो उसके विरोध का स्वर भी कहीं न कहीं हमें सुनाई दिया।..(व्यवधान).. मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जहां तक हिन्दुस्तान के विकास का प्रश्न है, कम-से-कम विकास के विषय पर उनको आगे आना चाहिए। ..(व्यवधान).. यह देश इस बात का साक्षी है कि जब भी देश में लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का काम हुआ है, स्वर्णिम अक्षरों में वह काला, ..(व्यवधान) इतिहास कांग्रेस के नाम पर लिखा हुआ है। ..(व्यवधान)..इसलिए हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की आवाज़ को आप किसी प्रकार से दबा नहीं सकते। थोड़े समय के लिए कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हर समय लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। मैं पुन: कहना चाहूंगा कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की नीतियां आज सबके सामने उजागर हुई हैं। ..(व्यवधान).. हमारी सरकार गरीबों के हित के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनैतिक विचारों के अनुरूप कार्य कर रही है।

अंत में मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि देश के विकास का मंत्र महात्मा गांधी देकर गए थे। महात्मा गांधी जी ने कहा था - 'मैं आप लोगों को एक ताबीज़ देता हूं कि जब भी आप कोई योजना बनाएं तो अपने मन में समाज के सबसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चित्र को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना।' ..(व्यवधान).. मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की

जो भी योजना बनी है, वह हमेशा देश के गरीब आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर बनी है।

(2H/DS द्वारा जारी)

DS-SSS/4.10/2H

श्री भूपेन्द्र यादव (क्रमागत) : आप उस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी कर सकते हैं, ...(व्यवधान)... लेकिन देश के गरीब का आर्थिक सशक्तिकरण और देश के हर वर्ग का सामाजिक समायोजन करने के लिए जो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, उसको आप रोक नहीं सकते, ...(व्यवधान)... क्योंकि देश की जनता का आशीर्वाद और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार और प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के साथ है। ...(व्यवधान)... बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please go back to your seats. ...(Interruptions)... Please go back to your seats.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जनरल बजट पर हमारी पार्टी के सदन के नेता, माननीय प्रो. राम गोपाल यादव जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ...(व्यवधान)...

मान्यवर, यह एक जनरल बजट है। पूरे देश की जनता बजट को सुनना चाहती है। मैं यह उम्मीद करता था कि देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी बोलेंगे, लेकिन उनको भी बोलने नहीं दिया गया। जिस तरह से यहाँ सदन में एक दूसरे पर टीका-टिप्पणी, चोर-सिपाही की लड़ाई चालू की गई है, यह देश के लिए दुर्भाग्य है। सदन

इसलिए है कि यहाँ देश के गरीबों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, देश की भुखमरी पर चर्चा होनी चाहिए, देश के कुपोषण पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन, आज देश में गाय-गोबर पर चर्चा हो रही है, बीफ पर चर्चा हो रही है, हिन्दू-मुसलमान पर चर्चा हो रही है, चोर-सिपाही पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, यह सदन कानून बनाने के लिए है। हम देश की जनता से कहना चाहेंगे कि जिस तरह दाहिने और बाएँ, दोनों तरफ से शोर हो रहा है, इन दोनों को हटाकर देश की जनता बीच के लोगों को सरकार बनाने का मौका दे, हम देश के गरीबों और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

मान्यवर, देश में ऐसे मौके आए हैं, जब बोफोर्स कांड को लेकर देश में सरकार बनी थी। इसी तरह, 2014 में केवल एक ही नारे पर, काले धन के नाम पर देश में मोदी जी की सरकार बनी थी। मोदी जी ने वादा किया था और कहा था कि हम काला धन वापस लाएँगे और 15-15 लाख रुपये सबके खाते में देने का काम करेंगे। महोदय, चार साल बीत गए, अब चुनाव का मौका आ गया। अब केवल जुमला रह गया, किसी के खाते में एक रुपया भी नहीं पहुँचा। माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी ने 12-प्वाइंट पर माननीय वित्त मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी से जवाब माँगा है। मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। आदम गोन्डवी जी का एक शेर है- *"तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आँकड़े असत्य, तेरा दावा किताबी है।"* यह जो बजट है, यह केवल किताबी है, यह आँकड़ों का मकड़जाल है।

महोदय, अभी भूपेन्द्र जी जन-धन खातों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। जब आपने घोषणा कर दी कि 15 लाख रुपये आएँगे, तो एक तरफ से लोगों ने जन-धन खाते

खुलवाने चालू किए। 30 करोड़ खातों में से 24 करोड़ खाते सक्रिय हैं और धीरे-धीरे वे भी बन्द हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है। वे सोचते हैं कि चुनाव आ गया है, अब किसी के खाते में 15 लाख रुपये आने वाले नहीं हैं। मान्यवर, इसी तरह से "स्वच्छता अभियान" में 12-15 हज़ार रुपये में शौचालय कैसे बनेगा, जबकि महँगाई इतनी चरम-सीमा पर चली गई है? बालू के रेट्स 10-गुना बढ़ गए और अब 10-15 हज़ार रुपये में एक ट्रॉली बालू आ रहा है। अगर लोहा, सीमेंट, उसकी शीट और चादर आदि का खर्च जोड़ लिया जाए, तो वह कुल मिलाकर 25-30 हज़ार रुपये में बनता है। मान्यवर, इन्होंने केवल प्रचार में 550 करोड़ रुपये खर्च करने का काम किया है।

(2जे/एमसीएम पर जारी)

MCM-NBR/2J/4.15

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : इसी तरह से उज्ज्वला योजना चलाई। इस बारे में काफी किताबी आंकड़े हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन के नाम पर सरकार ठगी कर रही है। पहला गैस कनेक्शन मुफ्त, दूसरे में पहले का भी चार्ज वसूलने का काम साढ़े तीन लाख लोगों में से आधे से भी ज्यादा लोग गैस सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। यह पिछला रिकॉर्ड है। तो फिर आगे लोग कैसे गैस कनेक्शन कराएंगे?

महोदय, इसी तरह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है। इस योजना में हम देख रहे हैं कि केवल बीमा कम्पनियों को फायदा हुआ। बीमा कम्पनियां जितना प्रीमियम ले रही हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा, उससे कम भुगतान हो रहा है। इसी तरह से 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना है। मान्यवर, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए थे, वित्त मंत्री

जी नहीं हैं। अगर ये किसी दिन डा0 राममनोहर लोहिया अस्पताल चले जाएं, क्योंकि देश के बड़े नेता है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वैसे इनको फुर्सत नहीं है किसी पब्लिक अस्पताल में जाने की। हम वहां गए हैं और देखा है कि पर्चा बनवाने के लिए रात के तीन बजे से लाइन लगती है। कितने लोगों का पर्चा बन पाता है और डॉक्टर्स एक दिन में कितने लोगों को देख पाता है? पूरे देश में जितने सरकारी चिकित्सालय, अस्पताल हैं, उनमें न पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, न दवाइयां हैं, न ईक्विपमेंट्स हैं। आप कैसे इलाज करोगे? केवल प्राइवेट बीमा कम्पनियों को ले आओगे और उनको ठगी करने के लिए छोड़ दोगे?

इसी तरह से ये मुद्रा बैंक योजना लाए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां के हमारे वित्त मंत्री जी बन गए हैं। चले जाओ अपने गोरखपुर में ही, किसी बैंक से अगर लोन लेना है तो कोई भी बिना कमीशन के कोई भी बैंक मैनेजर फाइल स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी मुद्रा योजना भी फेल हो गई है। इसी तरह से प्रधान मंत्री सिंचाई योजना जमीन पर नहीं उतरी है। इसको चार साल बीत गए हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, निराश हो गया है। मान्यवर, 30 नदियों को जोड़ने का कुछ अता-पता नहीं है, न बजट का पता है, न नदियों का पता है कि कहां जोड़ी जा रही हैं, क्या हो रहा है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Ramesh, please go back to your seats. You are all tired.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, ई-मंडी है, हमारे देश में किसानों की फसल बरबाद होती है। जब उनके पास फसल होती है तो उसका कोई खरीदार नहीं होता।

औने-पौने दामों पर बिचौलिए खरीदने का काम करते हैं। जो सरकारी आढ़ती और सरकारी केन्द्र हैं, उनमें कोई खरीद नहीं होती। उनमें खरीद या तो बड़े आदमी की होती है, व्यापारियों की होती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जिस तरह से नोटबंदी लागू हुई। पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट किस के बदले गए? बड़े-बड़े उद्योगपतियों के। क्या वे लाइनों में कभी लगे? लाइनों में वे लगे जो गरीब थे और दो हजार रुपए लेने के लिए कुछ तो शहीद हो गए। कुछ महिलाओं का बच्चा बैंकों की लाइनों में ही पैदा हो गया।

मान्यवर, इनकी ये सब योजनाएं फ्लॉप हैं। डेयरी के लिए कामधेनु योजना उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने चालू की थी। इन्होंने कामधेनु योजना को बंद करने का काम किया है।

मान्यवर, गायों की बात करते हैं। आज बाजार में कोई गाय नहीं बिक रही है। अगर कोई दुधारू गाय बाजार से लेकर अपने घर जा रहा है, तो कुछ तथाकथित लोग उन लोगों की हत्या करने का काम करते हैं। आज पूरे देश में लोग दहशत में हैं। तो कैसे दूध की बढ़ोतरी होगी, कैसे इनकी डेयरी सफल होगी। किसानों की फसलों पर लागत का डेढ़ गुना देने की बात की गई। मान्यवर, अब तक चार साल तो बीत गए। अभी तक चाहे विदर्भ हो, चाहे बुंदेलखड हो, माननीय वित्त मंत्री जी, हमारे बुंदेलखंड जाकर वहां के हालात देखिए। आज वहां का किसान तबाह है, मर रहा है। वहां फसल सूख गई है, वर्षा आधारित खेती है। वहां के लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। आज किसी को उनकी उपज का लागत मूल्य सही नहीं मिल रहा है, जिस कारण वहां आत्महत्याएं हो रही हैं।

इसी तरह से बेरोजगारी के बारे में बताना चाहूंगा। देश के करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। उनके लिए पहली बार राज्य सभा में मैं प्राइवेट मेम्बर बिल लाया था। मैं उम्मीद करता था कि सत्ता पक्ष भी इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन आज जो बजट में ये नारा दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं, ये सब थोथे लग रहे हैं, असत्य हैं, गलत हैं तथा जुमले हैं।

(2K/SC पर जारी)

SC-USY/4.20/2K

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : मान्यवर, हमारे उस प्राइवेट मेंबर्स बिल को भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट से गिराने का काम किया था। ये बेरोजगारों के विरोधी हैं। इन्होंने यह वायदा किया था, प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम पांच साल में दस करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। आप बताइए कि दस करोड़ लोगों में से आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया है? आज नौकरियां घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? ये कह रहे हैं कि जिसकी उम्र पचास साल हो गयी है, जो सरकारी नौकर है, अगर उसके खिलाफ उसके अफसर ने कोई भी bad entry कर दी है तो उसको permanent retire कर दो, जबरिया रिटायर किया जाए। आज लाखों लोग रिटायर हो रहे हैं, उन्हें जबरिया रिटायर किया जा रहा है - नौकरी देना तो दूर की बात है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी आंकड़े दिए कि हर विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं। आज लाखों पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भरा नहीं जा रहा है।

मान्यवर, आज देश के हालात बहुत खराब हैं। आप चार साल से दुहाई दे रहे हैं, इन्होंने कई बार चर्चा की, हर मीटिंग में ये पाकिस्तान की चर्चा करते थे, इनके पास

हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की चर्चा करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। इन्होंने कहा था कि एक सिर के बदले में ये दस सिर लेकर आएंगे। चार साल में हमारे इतने फौजी शहीद हुए हैं, जितने 70 साल में हमारे नौजवान शहीद नहीं हुए। हम जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार पाकिस्तान से दोस्ती क्यों बनाए हुए है? सरकार वहां से चीनी खरीद रही है, हींग खरीद रही है, क्यों नहीं यह सब खरीदना बंद कर देते? एक तरफ आप उससे दोस्ती करते हैं और दूसरी तरफ घुड़की देते हैं। आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आप दोनों तरफ बात करते हैं। आप वहां से चीनी मंगा रहे हैं, हींग मंगा रहे हैं, यहां से वहां साड़ी भेज रहे हैं, बिंदी भेज रहे हैं - यह क्या चक्कर है? आप देश की जनता से कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जबकि हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं।

मान्यवर, आज देश का गन्ना किसान मर रहा है, यहां का चीनी उद्योग पूरी तरह से बरबाद हो गया है। आज बुंदेलखंड में भुखमरी है, गरीबी है, किसान घाटे की खेती कर रहा है। हमने कई बार देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एससी/एसटी के लोग हैं, उनके संबंध में चर्चा की। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड क्लास का कोई व्यक्ति है तो यहां दिल्ली में वह बैकवर्ड क्लास का नहीं माना जाएगा, इस प्रकार पूरे देश में यह भिन्नता है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसमें एकरूपता लाने का काम करें। सारे देश में लोग नौकरी के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। इस कारण से उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये तमाम समस्याएं हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को आरक्षण

के लिए संस्तुति भेजने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लटकाने का काम किया है। हम चाहेंगे कि उसको बहाल किया जाए।

मान्वयर, इन्होंने टीबी की चर्चा की - बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश में सबसे बड़ी भयावह बीमारी कौन सी है - कैंसर। आज आप जिस किसी अस्पताल में भी चले जाएं, अगर वहां 500 रोगी होंगे तो 500 रोगियों में से 50 रोगी आपको कैंसर से पीड़ित मिलेंगे। कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए आपके पास अस्पताल नहीं हैं, मुम्बई में टाटा मेमोरियल अस्पताल है, वही पूरा देश देख रहा है, एम्स में कुछ व्यवस्था है, लेकिन कैंसर के अस्पतालों की दिक्कत है, उसके लिए सरकार को इंतज़ाम करना चाहिए।

मान्यवर, बजट में किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुणा लाभकारी मूल्य देने का वादा लोक सभा चुनाव में किया गया था। उसी दौरान...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Nishad, please yield for a minute. The hon. Minister wants to say something.

श्री नीरज शेखर : सर, फिर उनका समय रोक दीजिए।..(व्यवधान)..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIJAY GOEL) : Sir, in the morning, we had assured these Members, standing here, that the hon. Finance Minister would respond to their demands in his Budget reply. So, please ask them to go back to their seats.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): In view of the hon. Minister's assurance, please resume your seats. ….(Interruptions)… Please resume your seats. ….(Interruptions)…

SHRI C.M. RAMESH: Just one minute, Sir. I want to say something. ….(Interruptions)…

श्री आलोक तिवारी : पहले इन्हें समाप्त करने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, पहले हमारा भाषण complete होने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Ramesh*ji,* let him finish his speech first. Vishambhar*ji,* you please resume your speech.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, सब flop हो गयी हैं। फसल बीमा से केवल बीमा कम्पनियों को फायदा हो रहा है, किसानों को उनका फायदा नहीं मिल रहा है। फसल बीमा योजना किसानों के लिए कम, बीमा बाज़ार के लिए अधिक मुनाफे का सौदा है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 40 प्रतिशत बीमा दावों में भुगतान की जिम्मेदारी दी है, जिसमें कई राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया तो कैसे आपकी फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी?

(2एल-पीआरबी पर जारी)

PRB-PK/2L/4.25

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत): मान्यवर, पहले से किसान का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्मय से फसल बीमा होता था। उस अनुभव के आधार पर देय प्रीमियम से कम दावे बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। पिछले दो मौसमों में राज्य

सरकार और केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को 20,374 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जिसमें दावे 5,650.37 करोड़ के हुए, जिसमें केवल 53.94 लाख किसानों का फायदा हुआ। इसी तरह से निजी कंपनियों ने पूरे देश में advertise किया, प्रचार किया, शोर मचाया कि हम प्रीमियम की राशि से कम से कम 200 गुना का भुगतान करेंगे, लेकिन बीमा कराने के बाद दावे से कम भुगतान हो रहा है। मान्यवर, 2016-17 में बीमा कंपनियों की आय 1.27 करोड़ थी और इस वित्तीय वर्ष में तीन लाख करोड़ हो गई है। इससे private बीमा कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। इन्होंने 1,14,953 किसानों को केवल 51.52 करोड़ का भुगतान किया है, जो प्रीमियम से कम है और उस प्रीमियम का 1.82 प्रतिशत है। अब आप बताइए कि कैसे इसको डेढ़ गुना करेंगे, जबकि 1.2 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को मिला है।

मान्यवर, लोक सभा और प्रदेश की चुनावों की सभाओं में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, 2016-17 में, 5500 करोड़ के विपरीत 2733.67 करोड़ के दावे किए गए। गत वर्ष 10 लाख करोड़ में से 671113.42 के ऋण के दावे हुए। बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण देने में आनाकानी की जाती है। मान्यवर, बिचौलियों के माध्मय से कमीशन लिया जाता है। ये कृषि जमीन परीक्षण की बात करते हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि देश में 648 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें 6 विषयवस्तु विशेषज्ञों का प्रावधान है। देश में कुल 4487 पदों में 1014 से ज्यादा पद रिक्त हैं। देश में 70 कृषि विश्वविद्यालयों की हालत बहुत खराब है। उनके पास मानक के अनुसार जमीन नहीं है और अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। केंद्रीय कृषि

विश्वविद्यालयों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में देखें, तो झांसी, अलीगढ़, बनारस, इलाहाबाद में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जबकि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी बुनायादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में फैज़ाबाद, कानपुर, बांदा, मथुरा के हालात बहुत खराब हैं, वहां पर मानकों के अनुसार अभी तक पूरी faculty नहीं है।

मान्यवर, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी बुरे हालात हैं, उनके पास पर्याप्त लैब नहीं हैं, technicians नहीं हैं। गैर-सरकारी संगठनों के केंद्र तथा सरकारी केंद्र के कृषि वैज्ञानिक या तो NGO के मालिकों के लिए काम करते हैं या राजनीतिक दलों के असरदार बड़े लोगों के कृषि फार्मों के लिए काम करते हैं। यह सब हवा-हवाई हो रहा है। जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके यहां कृषि वैज्ञानिक लगे हुए हैं और किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, देश में कृषि की तरह मत्स्य पालन और मत्स्य आखेट का काम करोड़ों किसान करते हैं, जिनको जल किसान भी कहा जाता है। चाहे नदियां हों, तालाब हों, झीलें हों, जलाशय हों या समुद्र हों, वे मत्स्य आखेट का काम करते हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। आए दिन श्रीलंका और पाकिस्तान की सेना मछुवारों को पकड़कर ले जाती है और आज भी हजारों fishermen श्रीलंका और पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उनको छुड़ाया जाना चाहिए और उनके हितों के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

मान्यवर, आज देश के हालात बहुत खराब हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो हम लोगों ने बजट में प्रावधान रखा था, वह बहुत कम था। इन्होंने 2014 में कहा था - आप देश के संविधान में संशोधन कर दें कि पांच साल का चुनाव न हो, आप आज ही संशोधन ले आएं कि 2019 का चुनाव न हो और 2022 में चुनाव हों, तब तो हम मान सकते हैं कि आप 2022 में 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 करोड़ तो आपके चले गए, वह जुमला हो गया लेकिन अब 70 लाख लोगों को नौकरी देने का जो 2022 तक वायदा किया गया है, वह भी आपने चुनाव के मौके पर किया है। हम जानते हैं कि गांव में जब प्रधान का चुनाव होता है, जब last में चुनाव का time रह जाता है, तो प्रधान क्या करता है? वह राशन कार्ड लेकर, उसके आवास के लिए, उसके शौचालय के लिए, उसके पट्टे के लिए फौरन ग्राम सभा की बैठक करके कार्यवाही में नाम दे देता है, वह सबके घर में कह देता है कि तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, मुझे प्रधान बनाना, इस बार मैं तुमको मकान दूंगा। वही हाल मोदी जी का है, इन्होंने 2014 में कहा था कि हम 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, किसानों को उनकी उपज डेढ़ गुना मूल्य देने का काम करेंगे। मान्यवर, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, केवल जुमला बोलने वाली रह गई है।

(2M/GS पर जारी)

GS-PB/2M/4.30

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत): मान्यवर, देश में जहां-जहां चुनाव हुए हैं, वहां पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभाएं की हैं। उन्होंने हर जगह पर 24 घंटे बिजली देने की बात कही है। आप बिजली का उत्पादन कर नहीं रहे हैं, तो कैसे आप बिजली देंगे?

आज उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी की सरकार थी - चित्रकूट जो भगवान राम की जन्मस्थली है, जहां के हम लोग रहने वाले हैं, वहां पर 24 घंटे बिजली रहा करती थी, आज वहां पर 15 घंटे, 20 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। वहां के साधु-संत बहुत परेशान हैं। वे कहते हैं कि हमारे लिए तो पुरानी सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार अच्छी थी।

मान्यवर, जिस तरह से इन्होंने लॉलीपॉप देने का काम किया है, वे बिहार गए थे, वहां पर कितने हजार करोड़ का वायदा करके आए थे कि हम बिहार के विकास के लिए पैसा देंगे, लेकिन चुनाव के बाद कह दिया कि वह तो चुनावी जुमला था। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने नि:शुल्क बिजली देने का काम किया, नि:शुल्क नहरों से पानी देने का काम किया, नि:शुल्क ट्यूबवैल्स से पानी देने का काम किया, 15 लाख से ज्यादा समाजवादी पेंशन देने का काम किया और नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया था। मान्यवर, उनके द्वारा चलायी गयी सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। एक तरफ हमारे अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देने का काम किया और हमारे नरेन्द्र मोदी जी उनको पकौड़ा बेचने की सलाह देने का काम करते हैं। इन दोनों में अंतर है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज जो देश में महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, उसके निदान का बजट में कोई अता-पता नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी ने FDI की बात कही है और वे 100 प्रतिशत FDI देश में ले आए हैं। हमारे देश के जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, वे कहां जाएंगे?

देश में जीएसटी लगाने से पूरा व्यापार बरबाद हो गया है। हम कहना चाहते हैं कि आप जैसे 100 का नोट लाते हैं, आप 100 परसेंट की बात करते हैं, आप 28 परसेंट जीएसटी लगा देते हैं, आप पांच परसेंट ट्रांजेक्शन चार्ज लगा देते हैं, आप 20 परसेंट टैक्स लगा देते हैं, तो आप 100 रुपये के नोट में क्यों कहते हो कि मैं आपको 100 रुपये देने का वचन देता हूं, आप कह दीजिए कि हम 100 रुपये में केवल 43 रुपये देने का वचन देते हैं, बाकी तो आप टैक्स के रूप में काट ही रहे हैं, क्यों देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?

मान्यवर, जो 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क बीमा देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, वह एक जुमला है, खोखला है। इससे केवल बीमा कम्पनियों को फायदा होगा।

मान्यवर, आयुष्मान भारत के अंतर्गत सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और 24 नये मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले हमारे पुराने अस्पतालों को ठीक करवाने की व्यवस्था करवा दीजिए। यह केन्द्रीय बजट गरीब विरोधी बजट है, गरीब किसान, मजदूर विरोधी बजट है, बेरोजगारों और कारोबारियों की अनदेखी करने वाला बजट है, यह किसानों को छलने वाला और अमीरों को बढ़ावा देने वाला बजट है। देश में किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए उनके कर्जे माफ नहीं करना और 2022 के सपने दिखाना, यह जमीनी हकीकत से दूर है, इसलिए मैं इस बजट भाषण के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपने जनता से वायदे किए हैं, वे वायदे जमीन पर नहीं उतरे हैं, धरातल पर नहीं उतरे हैं और 2019 के इलेक्शन में जनता आपको बता देगी। जो चोर-सिपाही का खेल चल

रहा है, यह बंद होना चाहिए। इस देश से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you Vishambharji. Now, Shri S.R. Balasubramoniyan. …(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, till what time are we continuing today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): 8 o'clock.

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, Sir, on the eve of the Budget presentation, there are great expectations -- creation of jobs, a rise in income tax limit and so on and so forth. But contrary to expectations, there is no effort to create any job here. As far as income tax is concerned, the present Ruling Party used to say that income tax limits should be raised from two lakh to five lakh rupees, for the last five years. When they were in the Opposition and the UPA was in their place, they were repeatedly saying that. So, one expected that, at least, in the fourth year's Budget, the slab will be raised. But the slab was not raised. However, I must admit that standard deduction was raised to Rs. 40,000. But, at the same time, the education cess was raised from 3 per cent to 4 per cent. By raising standard deduction to Rs.40,000, the Government is expected to lose about Rs. 8,000 crores a year and by raising this one per

cent cess, the Government will get Rs.11,000 crores a year. So, they are giving from one hand and taking it from the other hand. That is the position. Transport allowance of Rs.19,200 and medical reimbursement of Rs.15,000 given under Section 72 are taken away.

(Contd. by 2n/SKC)

SKC-/2N/4.35

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Contd.): Basic excise duty on petrol and diesel was two rupees and additional excise duty, six rupees. Taken together, it comes to eight rupees. That was also taken away. They gave some relief, but again they have brought a cess. The long-term capital gains tax has also come. Now, I would like to mention certain other things.

The hon. President has mentioned the contribution the *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* has made in connecting the rural villages by roads. Ensuring road connectivity is the first step towards network connectivity and other things would follow. So, definitely, the Scheme must be welcomed and it must be carried out in a proper way. The GST Council has been responding positively with regard to the new suggestions of changes in the GST rates.

Sir, I would like to bring to the notice of the Union Government the practice of levying GST on projects executed for State Governments, which

amounts to a fiscal transfer from the States to the Union Government. In a way, it is a tax on the States, paid from the taxes collected from the people. Moreover, it also adversely affects the financial capacity of the States to execute works. I, therefore, request the Union Government to exempt projects executed for State Governments from the purview of the GST. There is another thing. When we give money out of MPLADS for the execution of works, there also the tax comes in. It is also considered for GST. So, these taxes must be definitely given up, so that the entire amount earmarked for the schemes are properly utilized. Post the Fourteenth Finance Commission recommendations, when the share in vertical devolution of Central taxes was increased from 32 per cent to 42 per cent, hon. Members may recollect, that the Government of India had reduced its share in the Centrally Sponsored Schemes from 75 per cent to 60 per cent. This was done by the Government of India unilaterally on the pretext that the States had obtained additional fiscal space due to the increase in the devolution to States from 32 per cent to 42 per cent. Unfortunately, a few States like Tamil Nadu had suffered badly due to the Fourteenth Finance Commission's recommendations, wherein the share of horizontal devolution for Tamil Nadu was reduced from 4.969 per cent to 4.023 per cent. So, we lose a heavy amount. This can be corrected by the Finance Commission

itself, or the Central Government could consider this issue and see to it that justice is done to States like Tamil Nadu. It is just a few States, not all, like Tamil Nadu, which are losing out. Such significant reduction in allocations has been noticed only in the case of a few States like Tamil Nadu. Therefore, the Finance Commission, with reputed economists, should have identified this shortcoming and should have provided a compensation mechanism to assure a minimum level of increase in devolution to all the States. This failure should be corrected only by the Union Government to bring fairness in resource distribution. I request the hon. Union Finance Minister to provide a special *ad hoc* grant to such States including Tamil Nadu to ensure equity in Central allocation.

Sir, the hon. President, in his Address, has mentioned, 'My Government is working actively to remove economic insecurity among the poor, farmers'. I am glad that the Government of India is implementing the *Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana* to protect farmers from the vagaries of nature. I am sure that the State of Tamil Nadu will proactively work in meeting the objectives of the Government of India. However, I wish to inform this august House that the Government of India has reduced the budgetary allocations in some very important schemes like the *Rashtriya Krishi Vikas Yojana* when agriculture is the mainstay of this country. Also,

there are other major schemes which cater to the rural areas and the poor like the National Rural Livelihood Mission, the National Rural Drinking Water Programme and the National Urban Livelihood Mission, which have also suffered significant reduction in budgetary allocations in the last three years at the national level.

(CONTD. BY HK/2O)

HK/2O/4.40

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (CONTD.): The hon. President in his Address has mentioned that 'My Government is committed to strengthening and modernizing school education system in the country.' However, the Union Government has not increased the allocations for schemes like *Sarva Shiksha Abhiyan* and *Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan* over the last three years and they have been largely stagnant. The investments we make in education sector are long-term investments, and if we do not make adequate allocations now, we may have to sacrifice on the economic development in the long run. I, therefore, request the Government of India to significantly increase the allocations for these vital schemes. I also wish to point out that many Ministries have not been making release of funds for the Centrally-sponsored schemes to States that have been committed by them on the ground that they have exhausted their budgetary allocations.

This is really unfortunate as it affects the resource planning of the State Governments. Consequently, there is a huge backlog in release of grants from the Centre, adversely affecting the implementation of the schemes. Tamil Nadu alone has pending arrears of Rs.6,696 crore to be received from the Government of India under various Centrally-sponsored schemes which are pending for more than a year. I would like to state a few examples for the consideration of the hon. Finance Minister of India. Under the post-matric scholarship scheme, an amount of Rs.1,547 crore is pending for Scheduled Castes for more than a year. The annual allocation in the Budget is grossly inadequate. There are pending arrears of Rs.1,312 crore under the SSA and Rs.1,588 crore under the RMSA for projects that have been approved by Central Project Approval Board. Almost Rs.3,000 crore are pending for that State. The Government of India had sanctioned construction of five fishing harbours in Tamil Nadu at a cost of Rs.521 crore, of which the Central commitment is Rs.298 crore. Though the construction of the fishing harbours is nearing completion, release of another Rs.143 crore is still pending due to under-budgeting by the Ministry of Finance. I, therefore, request the Union Finance Minister to make adequate budgetary provision to the above Ministries to enable the Central Ministries to honour the commitments made by them to the States. Hon. President has

mentioned that under the Metro rail programme, works are in progress in 11 cities. Metro rail project is being implemented in Chennai, and parts of the project are under commercial operations now. The project has transformed public transportation system in the city of Chennai and further, for strengthening the Metro rail network, the Government of Tamil Nadu has recommended to the Union Government to sanction phase-II of the Chennai Metro Rail Project, and I request the Union Government to approve this project. I am glad that the Government has approved the *'Bharatmala'*, an ambitious Highways Development Programme at a cost of Rs.5.35 lakh crore. I come to understand that projects for a cost of Rs.40,000 crore have been approved under this programme in Tamil Nadu, including the three new elevated corridors in Chennai, and the Chennai-Bengaluru expressway. I request the Government to expedite the execution of these projects and I am sure that the Government of Tamil Nadu will provide full support for land acquisition for these works. Thank you.

(Ends)

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (WEST BENGAL): Hon. Vice-Chairman, Sir, this is my maiden speech in this august House. I heard the deliberations from very famous personalities from both the sides, from my left and right, and tried to understand the implication of the Budget placed by the hon.

Finance Minister, Shri Arun Jaitley. Ours is a country which is governed by the people.

(Contd. by DPS/2P)

DPS/LP/2P/4.45

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (CONTD.): The Constitution was framed 'for the people, by the people, of the people'. The founding fathers of our Constitution thought that our great country will be governed for the interest of the people in the rural India or in urban India, for the youths and students, for kisans or labour force, for technologists or agricultural farmers, in the same tune as they desire. I served as a Member of the Legislative Assembly in West Bengal for six terms, that is, thirty years. I took part in the deliberations of the Budget, not less than eighteen times, to initiate as an Opposition Member. But the prevailing situation in this august House today gave a very strong pain in my heart today, where it was not in order. It is the apex House represented by the representatives of our country either from the literary world or from the political background, both are the representatives of the people - indirectly or directly. I came here to learn something to improve myself and to deliver the goods properly on behalf of my party led by Ms. Mamata Banerjee, the hon. Chief Minister of our State. On my left, Mr. M.J. Akbar is sitting. He is listening. Analyzing the basic

conceptual thoughts of the Budget, I think that it is against the concept of federalism. The entire concept, as I understand, it may be wrong or it may be right, but to me, it is absolutely against the concept of federalism. We protest it. Our Chief Minister protested, first in a loud voice that demonetization would have a catastrophic implication on the entire economic progress growth of our country. And it happened. More than 200 people committed suicide in India. In our country, we have 6,49,481 villages; towns, 7,935; Assembly constituencies, 4,120; and there are 125 crore people. In this spreading out demographic context, if we analyze what was the effect of demonetization, in sudden stroke on the 8th November, 2016, on the people of India, not on the Government, not on the rulers, not on important political leaders, but on the people, unprivileged, poor, poorer, many people have committed suicide. We are having 1,38,000 bank branches spreading over the country and there are 6,49,481 villages, and our population is 125 crore. We have 2,736 ATMs and the population is 125 crore. The result was long queues, hour after hour, the people were crying. The old-age people became helpless. Many died on the spot or in their homes and many people died in the family and they died on the agricultural field by committing suicide. Their voice was not heard properly by the Government. Starting from the hon. Prime Minister to the Finance Minister

and the entire proud Government, they did not listen to the voice of the people and the Opposition. This is not a healthy symbol of the Parliamentary democracy.

(Contd. by KSK/2Q)

KSK/KLG/4.50/2Q

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (CONTD.): We protested that sudden implementation, hasty implementation, of the GST would not give any positive effect to the revenues and to the delivery of the budgetary provisions of our country as a whole. On all the 30 States, what was the effect? The Government's revenue is lacking by more than Rs.50,000 crore. It is not my version. It has come in the Economic Survey. So, our hon. Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, protested along with others, all important political leaders, including one of the best economists of the world and the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. He told categorically, "It is a monumental blunder." But, nobody listened to him. They were moving like a wolf of Spain. They did not bother about what the Opposition was saying. And, what is the effect? The effect is also the lack of revenue mop-up, affecting SGST in the States, CGST in the Centre and the Integrated GST as a whole. The result is that agricultural growth has come down from 4.2 per cent to 2.1 per cent. Industrial growth has come down to

4.4 per cent. Only the service sector has witnessed a little rise. Employment generation is in negative. I was listening to the former Finance Minister, Shri P. Chidambaram. He pointed out very important aspects. When the growth is coming down, how can the employment generation be high? This is the basic question. I belong to medical profession. I am not an economist, but I study the economy. I belong to a farmer's family. I live in a village. I am a medical professional. So, I see it from three angles - the people, the society and the problems they face. Hon. Finance Minister's mission is to strengthen agriculture, kisans, health, education, employment, MSME and infrastructure. But, where is the money? From where will it come? Will it come from the sky, or, will it come from other countries as donation? It is not reflected properly in the Budget. It is not explained.

Sir, I come from the State of West Bengal which has got the best health infrastructure. I was comparing the parameters and the data given by the Central Government, the CSO. I was looking at how the Union Government, with the help of the State Governments, running the show for the benefit of the people, for the prevention and treatment of diseases. The approach of the Central Government is ambiguous and confused. I cannot understand what they are thinking and what they are going to do. Hon. Finance Minister has proposed Ayushman Bharat programme. It sounds

good. I appreciate if it is implemented properly. Nobody can protest that. But, it has become very much doubtful because the previous year's announcement has gone to the black hole. It has not been implemented at all till now. Then, there was a scheme for health insurance up to one lakh, which is completely non-existent now. Sir, through you, I humbly ask hon. Finance Minister to clarify and enlighten us on how he is going to implement this Ayushman Bharat programme and from where he will get the funds. I appreciate the version of the hon. Member, who just spoke before me, that it will be a great benefit to the multinational insurance companies. It is for the multinational insurance companies, not for the benefit of the people. Sir, I have been a doctor. During my practice, I have seen that when a patient goes to the hospital, they first check whether he has got the health insurance card or not. If he does not have one, they will simply say, 'get lost'. If he has got the health insurance card, they will say, "Please come and get admitted". (Contd. by 2R – GSP)

GSP-AKG/2R/4.55

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (CONTD.): Within two, three years, the bill jumps, jumps and jumps to more than a few lakhs of rupees. The patient is lying there without any treatment. Doctors keep visiting, blood is taken, and, all parameters of examination in pathology, bio-chemistry and

radiology are completed but no treatment, and the bill is going up and up, which gives benefit to the insurance companies. The insurance amount gets over. Where from this money will come? Has the Reserve Bank of India got a special reserve fund for this programme of the hon. Finance Minister? Please tell us, we will be pleased to learn it, and, we will accept it.

Sir, now, I come to the issue of agriculture. He has given us a rosy picture that the income of the farmers will be doubled in 2022. Today, when I am making this speech in front of you in this august House, the growth of agriculture is 2.1 per cent. To provide the farmers double of their income in the present context, in 2022, the growth of agriculture shall have to be 12 per cent. This is the basic economic concept. Sir, I shall be grateful to the hon. Finance Minister if he enlightens us with his agricultural arithmetic and economic arithmetic to convince me and other Members in this august House as to how he will give effect to this in the agricultural sector.

Sir, now I come to the issue of employment. While sitting in the chamber of West Bengal Assembly, I heard the Budget speech of 2014, the Budget speech of 2015, the Budget speech of 2016, the Budget speech of 2017, and, now, the Budget speech of 2018, I have listened personally in this august House. I read it thoroughly in between the lines. I got the points. Where is the employment? Two crore in a year is supposed to be 10 crore

by 2019. So, at least, for 3 years, it is six crore, six crore, six crore. Sir, were six lakh appointments there? Any appointment? And, in this Budget, he again reiterated that the situation is such, the study is such, the effect is such that there may be employment of 70 lakhs. Where from will it come?

I was really enlightened by the explanation of Mr. Chidambaram that employment or job-creation means employment which is permanent in nature, which is having continuity in nature, which has fixed salary with all benefits given by the Ministry of Labour. So, if that is the thing, in reality, how will it be implemented? If we consider employment generation under MNREGA, 100 days job has to be considered as a permanent job, you can consider, because person-days created is good, but still lagging in different States.

Our State, West Bengal, under the leadership of hon. Chief Minister got first place in creation of 100 days' employment. In India, West Bengal secured first position in this oppressive federal situation. I mean it. It is oppressive because we are not getting help under the Constitutional privileges of concept of federalism. In West Bengal, we started with Rs. 2,03,000 crore debt burden. The Central Government has got enormous debt burden. I understand it; I studied it. We wanted and we prayed to the Central Government for some moratorium but it was neither considered nor

granted. Minimum sympathetic consideration was not given by the Central Government to our State, West Bengal. (Contd. By SK/2S)